THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में नई लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण

1804. **श्री राम नरेश यादव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की संख्या कितनी है जहां नई रेल लाइनें बिछाने तथा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना के सर्वेक्षण को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है/विचाराधीन है या भविष्य में तैयार किए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की योजनाओं को कब तक शुरू किए जाने की सभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में जिन मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और जिन्हें योजना आयोग को अनुमोदन के लिए भेजा गया है, वे इस प्रकार हैं :—

(1) इलाहाबाद वाराणसी

(2) सगौली-रकसौल और कप्तानगंज से गोरखपुर तक समानांतर बड़ी लाइन सहित मुज्जफरपुर-बगहा-कप्तानगंज ।

बढवल-सीतापुर खंड और कासगंज से अलीगढ तथा एटा तक नई बड़ी लाइन सहित कानपुर-कासगंज खंड में मीटर लाइन को बड़ी लाइन मे बदलने के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है । इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में निर्णय सर्वेक्षणों के परिणामों और आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

Backlog of SC/ST in Central Warehousing Corporation

1805. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of FOOD be pleased to refer to reply to Unstarred Question 2275 given in the Rajya Sabha on the 30th March, 1991 and state:

(a) whether the number of posts decreased/increased including backlog of Scheduled Castes/Scheduled Tribes of previous years; if so, the details thereof year-wise;

(b) whether all essential measures to fill up SC/ST vacancies/backlog had been taken;

(c) whether the SC|ST backlog has been filled up by general candidate without dereservation; and

(d) whether approved panels of Engineering personnel were available when quota of SC/ST was surrendered at the alter of reorganisation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (INDEPENDENT CHARGE) (SHRI TARUN GOGOI): (a) After re-organisation of the Engineering Division in 1987, there was no change in the number of posts during 1988 and 1989. In 1990, the net addition/reduction in the various posts was as follows:—

Addition	
Executive Engineer (Civil)	2
Executive Engineer (Electrical)	1
Assistant Engineer (Electrical)	3
Sectional Officer (Electrical)	3
Reduction	
Assistant Engineer (Civil)	2
Sectional Officer (Civil)	16

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Approved panels became available after Engineering Division was re-organised in July, 1987.